खण्ड-9, अंक-1, वर्ष-2021, मु0प्र0 126-130
D.O.I.: https://doi.org/10.22445/avsp.v9i1.23
SJIF (2021) : 7.247

सततीय विकास हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन और नियोजन

गुंजन पाण्डेय
अर्थशास्त्र विभाग, बी0एस0एन0वी0 पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ–226 001, उ0प्र0, भारत
shagunplusl@gmail.com

प्राप्ति तिथि–31.08.2021, स्वीकृति तिथि–08.10.2021

सार– पर्यावरण प्रबंधन सम्पूर्ण विश्व के लिए पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की योजना एक बहुत ही विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में बनानी होगी। सच्ची विकासोन्मुख योजना हमेशा एक तरफ आर्थिक वृद्धि और दूसरी ओर विकास तथा पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन लाने में मदद करती है। भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता, यदि वह पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता को अनदेखा करना चुनता है। इससे देश के प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग और दुरुपयोग से बचा जा सकेगा। यह पारिस्थितिकी पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को भी कम करता है। इस लेख में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा की गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि इन क्षेत्रों की उचित पर्यावरण योजना और प्रबंधन के साथ उनका कैसे समाधान किया जा सकता है।

बीज शब्द– सततीय विकास, पर्यावरणीय जोखिम, पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण

Regional Environmental Management and Planning Leading to Sustainable Development

Gunjan Pandey
Department of Economics, B.S.N.V. P.G.College, Lucknow-226 001, U.P., India
shagunplusl@gmail.com

Abstract- Environmental Management plays a significant role to resolve environmental problems in whole world. We have to plan the use of our natural resources in a very judicious manner. True development oriented planning always helps to bring about a balance between economic growth and development on one side and environmental conservation and preservation of natural resources on the other. India can not be come a developed country, if it chooses to ignore the need for environmental planning and management. This would avoid over use and misuse of the natural resources of the country. It also minimizes the impact of human activities on ecology. This paper discusses the environmental problems faced by the rural and urban areas and also as to how they can be tackled with proper Environmental planning and management of these regions.

Key words- sustainable development, environmental hazards, ecology, environmental conservation and preservation

1. **परिचय–** पर्यावरण प्रबंधन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की योजना एक बहुत ही विवेकपूर्ण व्यक्ति के रूप में बनानी होगी। सच्ची विकासोन्मुख योजना हमेशा आर्थिक विकास, विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन लाने में प्रभावी होती है। भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता, यदि वह पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता को अनदेखा करना चुनता है। इससे देश के प्राकृतिक संसाधनों के अति प्रयोग और दुरुपयोग से बचा जा सकेगा। यह पारिस्थितिकी पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को भी कम कर सकता है। इस लेख में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सम्मुख आने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा की गई है और साथ ही यह भी बताया गया है कि इन क्षेत्रों की उचित पर्यावरण योजना और प्रबंधन के साथ उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। यह लेख, परिचय के अलावा पांच खंडों में बांटा गया है। खंड–2 ग्रामीण क्षेत्रों के सामने आने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में सूचित करता है, खंड–3 शहरी क्षेत्रों पर पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित है, खंड–4 सरकार और अन्य संगठनों के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों पर प्रकाश डालता है खंड–5 सरकार और अन्य गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्यावरण को मिटाने के लिए किए गए नियोजन और प्रबंधन प्रयासों को सामने लाता है। खण्ड–6, निष्कर्ष में लेख के सार तथा उसके मुख्य बिन्दुओं को उद्घाटित करता है।[1]

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं–

1) कृषि गतिविधियों के विस्तार के कारण रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों का प्रभाव बढ़ गया है जिससे खाद्य–चक्र नष्ट हो रहा है और इसका नकारात्मक प्रभाव जन जीवन पर पड़ रहा है।
2) ये हानिकारक रसायन पानी में घुल जाते हैं और मिट्टी द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जिससे भूमि की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।
3) लवणीयता का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे मरुस्थल का निर्माण और प्रसार होता है।
4) वनस्पति क्षेत्र धीरे–धीरे सिकुड़ रहा है क्योंकि बढ़ती आबादी के कारण आवास, परिवहन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। इससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर के प्रयासों में गिरावट हुई है।

3. शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं–

1) आवास सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है, इन क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए प्लास्टिक, पॉलिथीन और लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण फैल रहा है।
2) इन बस्तियों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे नदियों, पोखरों, तालाबों व अन्य जलाशयों में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है।
3) शहरों में बिजली और अन्य सुविधाओं के कारण आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होता रहता है।
4) ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास के कारण परिवहन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है जैसे वाहनों, पुलों, सड़कों, ओवर ब्रिज, रेल, ट्रकों की संख्या, इन सभी के कारण प्रदूषण में वृद्धि भी देखी जाती है।
5) नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के निरंतर प्रवास के कारण आवासीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, जिससे आवास बनाने के लिए कृषि भूमि का अर्जन व आसपास के तालाबों और पोखरों को भरा जा रहा है। इस प्रकार पानी के प्राकृतिक स्रोतों में कमी के कारण आने वाले समय में स्वच्छ जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है एवं कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
6) सड़कों, घरों, कार्यालयों, मनोरंजन केंद्रों के निर्माण के कारण हरे भरे स्थान कम होते जा रहे हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
7) वानस्पतिक क्षेत्र के लगातार सिकुड़ने के कारण शहरी क्षेत्र में भोजन चक्र टूट रहा है, जिससे इस पर निर्भर जीवों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है जो कि खाद्य चक्र का हिस्सा थे और अब विलुप्त हो रहे हैं।
8) शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार के नेटवर्क के कारण पशु–पक्षी हानिकारक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिसे उनके व्यवहार और संख्या दोनों में प्रतिकूल रूप में देखा जाता है।

4. भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन–

एनएसएसओ 1999–2000 के अनुसार, भारत की 26-1% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे हैं–[2] भूमिहीनता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण प्रदूषण, लिंग भेद इत्यादि। इसके प्रभावित होने वाले समूह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे, तथा शारीरिक रूप से विकलांग।

सुधार हेतु उपाय निम्न हैं–

1) कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें और गरीबी को दूर किया जा सके।
2) अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जाए और कीमत स्तरों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाए।
3) सततीय विकास के अंतर्गत सामाजिक भागीदारी को विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सामाजिक रूप से वंचित समूहों का विकास शामिल किया जाना चाहिए।[1]
जनभागीदारी से संबद्ध संस्थाओं को विकसित और प्रोत्साहित किया जा सकता है जैसे पंचायती राज संस्थाएं, सहकारिताएं और स्वैच्छिक समूह, जो रोजगार, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। इन सहभागी संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे वर्गों को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, जैसे खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, खान मजदूर, हथकरघा बुनकर,

ग्रामीण कारीगर इत्यादि।[3]

इस दिशा में सरकार द्वारा किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं–

1) कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें और गरीबी को दूर किया जा सके।
2) अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जाए और कीमत स्तरों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाए।
3) सततीय विकास के अंतर्गत सामाजिक भागीदारी को विकास की प्रक्रिया में बढ़ाया जा सके, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सामाजिक रूप से वंचित समूहों का विकास शामिल किया जाना चाहिए।

जनभागीदारी से संबद्ध संस्थाओं को विकसित और प्रोत्साहित किया जा सकता है जैसे पंचायती राज संस्थाएं, सहकारिताएं और स्वैच्छिक समूह, जो रोजगार, गरीबी उन्मूलन और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें। इन सहभागी संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे वर्गों को प्रोत्साहित करना होना चाहिए, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, जैसे खेतिहर मजदूर, छोटे और सीमांत किसान, खान मजदूर, हथकरघा बुनकर, ग्रामीण कारीगर इत्यादि।[3]

जन संगठन की अनुपस्थिति का अर्थ है, जनसमूह जो निर्माण कार्य में लगे होते, कार्य की कमी को उजागर करते, स्पष्ट करते, समाधान तैयार करते और उन्हें लागू करते, इन सब में जन भागीदारी का पूर्णतः अभाव हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि सूचना एवं प्रसार, नवीन ज्ञान एवं प्रशिक्षण के साथ–साथ वैज्ञानिक एवं कानूनी ढांचे के माध्यम से गरीबों के हितों की रक्षा की जाए। भारत जैसे विकासशील देश में बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है। ये बिजली, पानी, यातायात, सड़कों, पुलों, बांधों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों से संबंधित आवश्यकताएं हैं। बिजली और पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बढ़ती आवश्यकता को संतुलित करने के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। पर्यावरण पर और पर्यावरण के माध्यम से विकास के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिससे सततीय विकास प्राप्त हो सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरण योजना और प्रबंधन ऐसा है कि एक ओर पर्यावरण की लागत असंगठित/गरीबों द्वारा वहन कि जाती है और दूसरी ओर अमीरों/जमीनदारों द्वारा इसका आनंद लिया जाता है उदाहरण के लिए, पर्यावरण क्षरण, जिसे वायु और जल प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है, सबसे अधिक गरीबों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अमीर लोग स्वच्छ हवा में रहते हैं। दूसरी ओर गरीब कम किराए वाले इलाकों में रहने को मजबूर हैं, जो कि अस्वच्छ मलिन बस्तियों के रूप में देखा जा सकता है।

इस प्रकार इस खंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि विकास के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, पर्यावरण पर उसके प्रभाव का आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। नई विकास योजनाओं में न केवल पारिस्थितिक लागत का आयाम शामिल होना चाहिए बल्कि लाभों का वितरण भी शामिल होना चाहिए। विकास परियोजनाओं के प्रयासों में भूख मिटाने, गरीबी कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके हानिकारक प्रभावों को क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार या अन्य गैर सरकारी संगठन को जिम्मेदारी दी जाए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन साथ ही विकास के अवसरों को सावधानी पूर्वक लागू किया जाए। चुनौती तब सामने आती है जब विकास परियोजना की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूख को दूर करने या गरीबी को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नुकसान स्थानीय गरीबों द्वारा वहन नहीं किया जाए या भविष्य की पीढ़ी पर नहीं डाला जाए। जिससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव न वर्तमान तथा भविष्य पर पड़ने पाए।

ग्रामीण आबादी का दबाव कृषि विविधीकरण और गहनता से होने वाले लाभ को कम कर देता है। परिणामस्वरूप कई जगहों पर प्राकृतिक संसाधनों के स्रोत कम होते जा रहे हैं। इस कारण ऐसे क्षेत्रों से शहर और उच्च कृषि उत्पादकता वाले अन्य क्षेत्रों में प्रवासन, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनो के दबाव पर एक और चुनौती उत्पन्न कर रहा है, जिससे निपटने की आवश्यकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार और योजनाविद् पर्यावरणीय शिक्षा पर जोर दें और ऐसा संगठनों को बल दिया जाए जिससे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यावरण नियोजन, प्रबंधन और विकास, नीतिगत पहल के रूप में किया जाए।

5. शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण–

भारत, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां देश है। भारत के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों को अपने पड़ोसी देशों

की तुलना में एक अलग पैमाने पर देखा जा सकता है, जिसमें समान विशेषताएं तो हैं पर सरकार का विकेन्द्रीकृत रूप भी है और कुछ भारत के प्रदेश पड़ोसी देशों से सामान्य सीमाओं से जुड़े हुए भी पाए जाते हैं।[5] भारत वर्तमान में एक मूल्यांकन रणनीति तैयार कर रहा है, यह देश में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुद्दों पर उपयोगी सूचना प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। पूरे भारत में शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। वायु और जल प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर और स्वच्छता सेवाओं की कमजोर स्थिति। ये तत्व उच्च मानव लागत को जन्म देते हैं, जिसे मानव स्वास्थ्य का निम्न स्तर और उच्च मृत्यु दर द्वारा देखा जा सकता है, यही उच्च लागत–प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सम्मिलित हैं। ये सभी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत भारत में प्रभाव आकलन सूचकांक के तहत पाए गए हैं। ब्रैंडन और वोमन 1995 ने भारत के कुछ प्रमुख पर्यावरणीय लागत संबंधी निर्धारक तत्व दिए हैं,[2] जिनमें से प्रमुख हैं; औद्योगिक विनाशकारी अपशिष्ट, मिट्टी का क्षरण, घास के मैदान का क्षरण, वनों की कटाई, तटीय जल संसाधनों का विनाश, जैव विविधता व पर्यटन की हानि। शहरीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय औद्योगीकरण की नीति को प्रोत्साहन मिला है। जिससे अस्थिर ग्रामीण विकास और बढ़ते प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जो औद्योगीकरण के कारण पाई जाती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास सुविधा में वृद्धि लाने के फलस्वरूप और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। इसका विश्लेषण यूएसएड–इंडिया और यूएस–एशिया एनवायरमेंटल पार्टनरशिप द्वारा किया गया था। भारत ने शहरीकरण के प्रतिकूल परिणामों की पहचान की है और देश की सहायता हेतु ऐसे कार्यक्रमों की मांग की जा रही है जिसमें सततीय विकास के लिए की गई शुरूआत शामिल है। इसमें गैस पाइपलाइन का प्रसार, स्वच्छता संबंधी इकाइयों की स्थापना शामिल है, इन प्रयासों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी शामिल है, जो अंततः वैश्विक पटल पर जलवायु परिवर्तन के स्तर को कम करने में सक्षम होगी।

ऊर्जा के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पहल (एस.ए.आर.आई.ई-) के अलावा, बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन और स्वच्छ और अधिक ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए भारत के चल रहे प्रयासों को समर्थन मिला है। इस संदर्भ में तीन प्रमुख क्षेत्रों को देखा जा सकता है जिसके अंतर्गत भारत के कार्यक्रमों और नीतियों द्वारा शहरी, औद्योगिक और ऊर्जा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है–[3]

क. शहरी या ग्रामीण दोनों ही स्थितियों में दुर्लभ जल संसाधनों के आवंटन और प्रबंधन पर प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता के रूप में उभर रही है। मुद्दा इस कारण से उठता है कि इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत में सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं की एक विस्तृत स्थिति पायी जाती है और देश के प्रत्येक क्षेत्र में पानी की एक अनूठी व्यवस्था पायी जाती है। सरकार का विकेन्द्रीकृत रूप भी समस्या को हल करने में मुश्किल का सामना कर रहा है क्योंकि संसाधनों को राज्य के भीतर और अंतर–राज्य स्तर पर कई क्षेत्रों द्वारा साझा किया जाता है। जल प्रबंधन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है।

ख. भारत के तेजी से औद्योगिक विकास और शहरी केंद्रों के विकास ने भारी स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है जो प्रकृति में पर्यावरणीय हैं। उनकी गणना इस प्रकार की जा सकती है; वायु प्रदूषण, अशुद्ध जल आपूर्ति, स्वच्छता के मुद्दे, इन वजहों से बढ़ी हुई बीमारियों और मृत्यु दर के माध्यम से सामाजिक लागत में वृद्धि हुई है। गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर समाज सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। शहरी विकास पर यूएसएआईडी की क्षेत्रीय गतिविधियां (दिल्ली बेस साउथ एशिया आरयूडीओ) और शहरी और औद्योगिक पर्यावरण प्रबंधन पर (यू0एस0ए0ए0ई0पी0के माध्यम से) हालांकि, स्वास्थ्य, बाल अस्तित्व, पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित कार्यक्रमों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बेहतर समन्वय की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी, ताकि बेहतर समझ हो सके।

ग.आपदा प्रबंधन भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत बाढ़, सूखा, हवा की क्षति, भूकंप से ग्रस्त है। मानव निर्मित आपदाएं एक और चिंता का विषय हैं। भारत में आपदा पूर्वानुमान और अग्रिम चेतावनी प्रणाली पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपदा तैयारी और ग्रामीण–शहरी नियोजन और प्रबंधन के बीच एक पूरकता है।

6. निष्कर्ष–

पर्यावरण पर विकास के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिससे सततीय विकास प्राप्त हो सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरण योजना और प्रबंधन ऐसा है कि एक ओर पर्यावरण की लागत असंगठित/गरीबों द्वारा वहन की जाती है और दूसरी ओर अमीरों/जमींदारों द्वारा इसका आनंद लिया जाता है उदाहरण के लिए, पर्यावरण क्षरण, जिसे वायु और जल प्रदूषण के रूप में देखा जा सकता है, सबसे अधिक गरीबों द्वारा वहन किया जाता है, जबकि अमीर लोग स्वच्छ हवा में रहते हैं। दूसरी ओर गरीब कम किराए वाले इलाकों में रहने को मजबूर हैं, जो कि अस्वच्छ मलिन बस्तियों के रूप में देखा जा सकता है।

अतः विकास के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, पर्यावरण पर उसके प्रभाव का आंकलन करना आवश्यक हो जाता है। नई विकास योजनाओं में न केवल पारिस्थितिक लागत का आयाम शामिल होना चाहिए बल्कि लाभों का वितरण भी शामिल होना चाहिए। विकास परियोजनाओं के प्रयासों में भूख मिटाने, गरीबी कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि इसके हानिकारक प्रभावों को क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सरकार या अन्य गैर सरकारी संगठन को जिम्मेदारी दी जाए। अतः यह आवश्यक है कि सरकार और योजनाविद् पर्यावरणीय शिक्षा पर जोर दें और ऐसा संगठनों को बल दिया जाए जिससे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों का पर्यावरण नियोजन, प्रबंधन और विकास, नीतिगत पहल के रूप में किया जाए।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी पर्यावरण नियोजन और विकास हमारे देश के लिए आवश्यक है और सरकार को विनियमों और उसकी नीतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों को भी गरीबी उन्मूलन के सरकारी प्रयासों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पारिस्थितिक सद्भाव और संतुलन लाएगा और अंततः पर्यावरणीय स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ

1. अवस्थी, एन0 एम0 (2018) पर्यावरण अध्ययन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
2. यूजीन, टी0 ए0 (2011) पर्यावरण अर्थशास्त्र, वृंदा प्रकाशन प्रा0 लिमिटेड, दिल्ली।
3. झिंगन, एम0 एल0 ए0 (2016) पर्यावरण अर्थशास्त्र, वृंदा प्रकाशन प्रा0 लिमिटेड, दिल्ली।
4. केथल, ए0 के0 एवं कुमार, एस0 ए0 (2020) पर्यावरण अर्थशास्त्र केंद्र, लखनऊ।
5. सिन्हा, उदय प्रकाश (2007) सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण का अर्थशास्त्र, अवधारणा प्रकाशन कंपनी, नई दिल्ली।